To Complete the Development Works

***9. Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):-**

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that a file of Rupees 27.48 crore of development works of Faridabad NIT Assembly Constituency was forwarded by the Municipal Corporation, Faridabad to the Director, Urban Local Bodies Department vide letter no. MCF/SE/2023/978 dated 12/10/2023 regarding lack of funds in Municipal Corporation, Faridabad and the necessity of executing said works was also mentioned; and

b) if so, the present status of the said file togetherwith the time by which the said file is likely to be approved alongwith the time by which the abovesaid works are likely to be completed?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister

a) Yes sir.

b) The works come under the purview of the Municipal Corporation as per the priority list dated 01.06.2023 circulated by the Government. As on 30.11.2023, ₹ 626.59 Crore are available with Municipal Corporation, Faridabad. Government will provide additional grant to the Municipal Corporation, in case Municipal Corporation is unable to provide funds for the developments works in the municipal area.

विकास कार्यों को पूरा करना

***9. श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि नगर निगम, फरीदाबाद में निधि के अभाव के संबंध में नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को अपने पत्र क्रमांक एमसीएफ/एसई/2023/978 दिनांकित 12.10.2023 के माध्यम से एनआईटी विधानसभा के विकास कार्यो की 27.48 करोड रूपए की फाइल भेजी थी तथा उसमें उक्त कार्यो को करवाने की आवश्यकता भी वर्णित की गई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त फाइल की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त फाइल के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है तथा उपरोक्त कार्य कब तक पूरे किए जाने की संभावना है?

डा0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) सरकार द्वारा जारी प्राथमिकता सूची दिनांक 01.06.2023 के अनुसार कार्य नगर निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दिनांक 30.11.2023 तक, नगर निगम, फरीदाबाद के पास ₹ 626.59 करोड़ उपलब्ध हैं। यदि नगर निगम अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो सरकार नगर निगम को अतिरिक्त अनुदान देगी।